के लिये अनुसंधान संबंधी प्रयासों को तेज करना और तिलहन उत्पादन कार्यक्रम को गति के साथ-साथ चलने के लिये परिसंस्करण और अवसंरचना संबंधी सुविधाओं की स्थापना करना आदि।

(ख) राज्य व्यापार निगम द्वारा खरीद अपने यहां पंजीकृत अन्तर्राष्ट्रीय रूप से प्रतिष्ठित सप्लायरों से निविदाएं आमन्त्रित करने के बाद ही की जाती है। खाद्य तेलों के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में काफी उतार-चढ़ाव आता रहता है, जो विश्व की सप्लाई और मांग की स्थिति और अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं, अर्थात् मौसम की स्थितियों, बाजार में लगे धन और अन्य फसलों की उपलब्धि आदि, पर निर्भर करता है।

अतः, खाद्य तेलों के आयात मूल्य में भी काफी उतार-चढ़ाव आता रहता है। कितना किया जाये इसका निर्णय मांग, देशी तेलों की उपलब्धि और कुछ अन्य पहलुओं के आधार पर किया जाता है।

(ग) कोई ऐसी तकनीकी समिति गठित नहीं की गई है।

पन्ना (मध्य प्रदेश) में हीरे की खदानें

814. **श्री प्यारेलाल खंडेलवाल :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के प्रभावशील होने के बाद पन्ना में उथली हीरा खदानें खुदाई के लिये बंद कर दी गयी है तथा मध्य प्रदेश सरकार ने इन खदानों के पट्टे देना बंद कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके परिणामस्वरूप कितने खदान मजदूर बेरोजगार हो गये हैं ; और

(ग) क्या पन्ना के हीरा खदान क्षेत्रों में वन न होने के बावजूद भी वहां वन संरक्षण अधिनियम के उपबन्धों को लागू कर दिया गया है और यदि हां, तो इस क्षेत्र में इस अधिनियम के उपबन्धों को लागू करने के क्या कारण हैं ?

खान विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) (क) से (ग) : जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ?

Utilisation of water from Chambal Canal by Madhya Pradesh and Rajasthan

815. SHRI PYARELAL KHANDELWAL; V/UI the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state;

(a) what is the proportion in which Madhya Pradesh and Rajasthan have utilised water from Chambal Canal each year from 1977-78 to 1984-85;

(b) whether it is a fact that Madhya Pradesh is 'not getting adequate share of water;

(c) if so, what is the reason therefor;

(d) whether it ia also a fact that a field agency for water regulation as decided by M.P. and Rajasthan Inter-State Control Board has not yet been set up; and

(e) if so, what are the reasons therefor and the steps taken for its early constitution?

THE MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI B. SHANKARANAND); (a) It is reported that the States of Madhya Pradesh and Rajasthan have utilised water from the common Chambal Right Main Canal System, as given below:—

(In Million AM Feet)

Year	Rajasthan	Madhya Pradesh
1977-78 . . .	0.9780	1.3620
1978-79 . . .	1.1634	1.379
1979-80 . . .	0.9230	1.0520
1980-81 . . .	1.00	1.1980
1981-82 . . .	1.00	1.4571
1982-83 . . .	1.00	1.1764
1983-84 . .	1.0861	0.8905
1984-85 . . .	1.0964	1.1723

(b) and (c) Madhya Pradesh has been complaining that it is not receiving its share of water from Rajasthan during the time of peak Rabi demand due to excessive drawal by Rajasthan, in the upper reaches of the canal. But according to Rajasthan, Madhya Pradesh has been abstracting water upstream of Gandhi-sagar Dam, thereby reducing the inflows into the reservoir. However, except in one year as above, Madhya Pradesh has been getting more flows.

(d) Yes, Sir.

(e) It is for the two State' Governments to take a decision in the matter.

Production capacity of steel plants of SAIL

816. SHRI PYARELAL KHANDELWAL: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) what is the total production capacity of all the plants of Steel Authority of India Limited as on 31st March, 1986; and'

(b) what was the total actual production of the said plants during last year?

THE MINISTER OF STEEL AND MINES (SHRI K. C. PANT): (a) The total production capacity of saleable steel of all the steel plants of Steel Authority of India Limited (including HSCO) as on 31st March, 1986 was 7.2 million tonnes per annum.

(b) The total production of saleable steel of these plants in 1985-86 was 6.00 million tonnes. This production was 14 per cent more than in 1984-85.

कीटनाशक दवाइयों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्रयोगशालाएं

817. **श्री प्यारेलाल खंडेलवाल :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने विभिन्न राज्यों अथवा क्षेत्रों में कीटनाशक दवाइयों की गुणवत्ता नियंत्रण के लिये प्रयोगशालाएं स्थापित की हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनका राज्यवार ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इन प्रयोगशालाओं को स्थापित करते समय मध्य प्रदेश की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा गया था; यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ; और

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार ऐसी एक प्रयोगशाला मध्य प्रदेश में स्थापित करने का विचार रखती है और यदि हां, तो इसे कब तक स्थापित कर दिये जाने की संभावना है ?

कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा) : (क) राज्यों में जहां कहीं कीटनाशी परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं वे सब राज्य सरकारों द्वारा ही स्थापित की गई है । कीटनाशी अधिनियम की सांविधिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये केन्द्रीय सरकार ने फरीदाबाद (हरियाणा) में एक केन्द्रीय कीटनाशी प्रयोगशाला स्थापित की है, जिसका एक यूनिट बम्बई (महाराष्ट्र) और दूसरा यूनिट हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश) में है। केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों के प्रयासों में मदद करने के लिये पांच क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं की स्थापना करने के लिये पहले ही योजना को मंजूरी दे दी है।

(ख) विभिन्न केन्द्रीय प्रयोगशालायें जिन स्वीकृत स्थानों तथा राज्यों/संघ